

## इज़राइल कैसे आईसीसी के क्षेत्राधिकार से बचता है

क्या होगा यदि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी), जिसे दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों का अभियोजन करने का जिम्मा सौंपा गया है, एक राष्ट्र की चालाकी भरी चोरी के सामने असहाय हो? इज़राइल ने आईसीसी के पूरकता सिद्धांत को एक ढाल में बदल दिया है, जो नकली जांचों के साथ स्वतंत्र जांचों को बाधित करता है। यह निबंध खुलासा करता है कि इज़राइल इस कानूनी खामियों का शोषण कैसे करता है, एक दोहरी न्याय प्रणाली लागू करता है जो हिंसक बसने वालों को उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों पर तरजीह देती है, और अमेरिकी प्रतिबंधों पर निर्भर करता है जो SWIFT नेटवर्क, मास्टरकार्ड/वीजा, और उड़ान निषेध सूचियों के माध्यम से आईसीसी के न्यायाधीशों को पंगु बनाते हैं। हिंद राजब और राफा पैरामेडिक नरसंहार इस रणनीति की गहराई को उजागर करते हैं, जो तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करते हैं।

### पूरकता सिद्धांत का शोषण

आईसीसी का पूरकता सिद्धांत, जो रोम संनियम के अनुच्छेद 17 में निहित है, केवल तभी हस्तक्षेप की अनुमति देता है जब कोई राज्य अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अपराधों का “न तो इच्छुक हो और न ही सक्षम” हो। इज़राइल इस प्रावधान का दोहन करता है, सतही आंतरिक जांचों को अंजाम देकर जो आईसीसी की निगरानी को विफल करने के लिए एक मुखौटा के रूप में काम करती हैं। जनवरी 2024 में हिंद राजब नरसंहार और 23 मार्च 2025 को राफा पैरामेडिक नरसंहार इस रणनीति के उदाहरण हैं। हिंद राजब मामले में, IDF ने शुरू में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि 6 साल की बच्ची और उसके परिवार को टैंक की गोलीबारी से मारने वाले स्थान के पास कोई सैनिक नहीं थे, और उन्हें बचाने के लिए भेजी गई एक एम्बुलेंस नष्ट कर दी गई, जिसमें दो पैरामेडिक्स की मौत हो गई। केवल वीडियो सबूत और फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स की स्वतंत्र जांचों के बाद, जिन्होंने IDF टैंक की जिम्मेदारी साबित की, IDF ने “गलतियों” को स्वीकार किया, लेकिन कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया—केवल एक प्रारंभिक समीक्षा ने सैनिकों को गलती से मुक्त कर दिया। इसी तरह, राफा नरसंहार में, IDF ने झूठा दावा किया कि मानवीय वाहन “संदिग्ध” थे और हमास से जुड़े थे, जिसमें 15 सहायता कार्यकर्ताओं, जिसमें PRCS और UN कर्मचारी शामिल थे, को निष्पादन शैली के हमले में मार डाला गया। बाद में वीडियो फुटेज ने इस कथन का खंडन किया, जिसने IDF को त्रुटियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसकी 20 अप्रैल 2025 की जांच केवल “पेशेवर कदाचार” के निष्कर्षों के साथ समाप्त हुई, जिसमें एक डिप्टी कमांडर को हटा दिया गया और दूसरे को बिना आपराधिक जवाबदेही के अनुशासित किया गया।

ये जांच न तो स्वतंत्र हैं और न ही कठोर, क्योंकि वे सैनिकों की स्व-हितकारी गवाही पर निर्भर करती हैं, जबकि पीड़ितों के सबूत और मानवाधिकार रिपोर्टों को खारिज कर दिया जाता है। IDF का पैटर्न—2008-2009 की गाजा युद्ध के बाद 47 जांच शुरू करना और 1% से कम अभियोग—इसकी वास्तविक अभियोजन करने की अनिच्छा को रेखांकित करता है। इज़राइल इसके अलावा ICC की प्राधिकरण को चुनौती देता है, 2015 में रोम संनियम में फिलिस्तीन के शामिल होने के बावजूद उसकी राज्य की स्थिति पर विवाद करता है, एक रुख जिसे प्री-ट्रायल चैंबर I ने 21 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया, जब इसने क्षेत्राधिकार की पुष्टि की और नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों ने ICC के न्यायाधीशों को निशाना बनाया, जैसा कि 5 जून 2025 को विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषित किया, इस उचट को और बढ़ा दिया। ये उपाय, जो जजों सोलोमी बालुंगी बोस्सा, लूज़ डेल कारमेन इबानेज़ करान्ज़ा, रेन एडिलेड सोफी अलापिनी गांसू, और बेंटी होहलर को लक्षित करते हैं, अमेरिकी संपत्तियों को अवरुद्ध करते हैं और यात्रा प्रतिबंध लगाते हैं, संभवतः SWIFT नेटवर्क के माध्यम से उनके बैंक खातों को फ्रीज करते हैं और मास्टरकार्ड/वीजा सेवाओं को निलंबित करते हैं, जैसा कि अभियोजक खान के बाधित पहुंच के मामले में देखा गया। यह अमेरिकी समर्थन, जो संप्रभुता के दावों में निहित है, ICC की कार्यवाही में देरी करता है, इज़राइल की उचट को एक जानबूझकर पूरकता के दुरुपयोग के रूप में मजबूत करता है ताकि प्रलेखित अत्याचारों के लिए न्याय से बचा जा सके।

### भिन्न न्यायिक मानक: फिलिस्तीनी बनाम हिंसक बसने वाले

इज़राइल की न्यायिक प्रणाली एक उत्पीड़न के उपकरण के रूप में कार्य करती है, एक दोहरी कानूनी व्यवस्था लागू करती है जो कब्जे वाले क्षेत्रों में चौथे जेनेवा कन्वेंशन के समान संरक्षण के लिए आदेश का उल्लंघन करती है। फिलिस्तीनी, जिनमें 12 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, एक सैन्यीकृत अदालत प्रणाली के अधीन हैं जो पत्थर फेंकने जैसे छोटे अपराधों को

कठोर उपायों से दंडित करती है। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन फिलिस्तीन की रिपोर्ट है कि प्रतिवर्ष 500-700 बच्चों को हिरासत में लिया जाता है, जो हिंसा, एकांत कारावास और बिना कानूनी प्रतिनिधित्व के जबरन स्वीकारोक्ति का सामना करते हैं, जैसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की 2015 की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के दुरुपयोगों पर प्रलेखित किया गया है। 2022 में, 137 बच्चों को हिरासत में लिया गया, और 2023 में एक घातक वृद्धि देखी गई, जिसमें नाबालिगों की स्नाइपर द्वारा हत्या शामिल थी, जैसा कि द गार्जियन की 2024 की खोज में बताया गया। ये मामले अक्सर कारावास में समाप्त होते हैं, जो बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन का उल्लंघन करता है।

इसके विपरीत, हिंसक इज़राइली बसने वाले—पश्चिमी तट में 700,000 से अधिक—नागरिक कानून के तहत काम करते हैं, और जमीन हड़पने और हमलों के लिए दण्डमुक्ति का आनंद लेते हैं। बी'त्सेलेम की 2021 की रिपोर्ट, "यहूदी वर्चस्व का शासन," विस्तार से बताती है कि कैसे बसने वाले, हथियारबंद और IDF चौकियों द्वारा समर्थित, आगजनी, पिटाई और हत्याओं के माध्यम से पश्चिमी तट की 50% से अधिक जमीन पर कब्जा करते हैं। 2015 में दूमा में आगजनी हमले, जिसमें एक फिलिस्तीनी परिवार की मौत हो गई, में वर्षों की देरी के बाद केवल एक बसने वाले को सजा हुई, जबकि अन्य लोग न्याय से बच गए। अड्दामीर की 2023 की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि सैन्य अदालतें बसने वालों को बाहर रखती हैं, जो हल्की नागरिक कार्यवाही या बिल्कुल कोई कार्यवाही से लाभान्वित होते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा भूमि जब्ती को "सुरक्षा" उपायों के रूप में मंजूरी दी जाती है। यह असमानता एक नस्लीय प्रभुत्व की व्यवस्था को मजबूत करती है, जो रोम संनियम की अपराध परिभाषा का स्पष्ट उल्लंघन है।

### केस स्टडी: हिंद राजब और राफा पैरामेडिक नरसंहार

हिंद राजब और राफा पैरामेडिक नरसंहार इज़राइल की चोरी की रणनीतियों के भयानक उदाहरण हैं। जनवरी 2024 में, हिंद, एक 6 साल की लड़की, और उसका परिवार गाजा शहर में IDF टैंक की गोलीबारी से मारे गए, और एक बचाव प्रयास में भेजी गई एम्बुलेंस भी निशाना बनाई गई, जिसमें पैरामेडिक्स यूसुफ ज़ीनो और अहमद अल-मधून मारे गए। IDF ने झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वहां कोई सैनिक नहीं थे, जब तक कि फॉरेंसिक आर्किटेक्चर की 2024 की जांच, वीडियो और ऑडियो सबूतों द्वारा समर्थित, ने इसके विपरीत साबित नहीं किया, यह दिखाते हुए कि टैंक ने 13-23 मीटर की दूरी से गोलीबारी की। कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया—सैनिकों को "पेशेवर कदाचार" के बहाने से मुक्त कर दिया गया। इसी तरह, 23 मार्च 2025 को राफा हमले में 15 सहायता कार्यकर्ता, जिसमें PRCS और UN कर्मचारी शामिल थे, एम्बुलेंस और एक UN वाहन पर हमले में मारे गए। IDF ने झूठा दावा किया कि हमला से संबंध था, लेकिन एक पैरामेडिक के फोन से वीडियो सबूत ने झूठ को उजागर किया, जिसमें वाहनों को रोशनी के साथ गोलीबारी के तहत दिखाया गया। 20 अप्रैल 2025 की जांच केवल "पेशेवर विफलताओं" पर समाप्त हुई, एक डिप्टी कमांडर को हटाया गया बिना आपराधिक जवाबदेही के, भले ही शवपरीक्षा ने जानबूझकर हत्याओं की पुष्टि की।

ये मामले इज़राइल के पैटर्न को उजागर करते हैं: तब तक झूठ बोलना जब तक कि निर्विवाद सबूत सामने न आएँ, फिर नकली जांचें करके अपराधियों को मुक्त करना, पूरकता का शोषण करके आईसीसी के क्षेत्राधिकार को अवरुद्ध करना। अमेरिकी प्रतिबंध जो आईसीसी के न्यायाधीशों की वित्तीय और यात्रा क्षमताओं को बाधित करते हैं, इस दण्डमुक्ति को और मजबूत करते हैं, जिससे अदालत कार्य करने में असमर्थ हो जाती है।

### कानूनी आधार और अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

इज़राइल के कार्य अपराध कन्वेंशन और रोम संनियम का उल्लंघन करते हैं, जो अपराध को एक नस्लीय समूह द्वारा दूसरे पर व्यवस्थित उत्पीड़न के रूप में परिभाषित करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2021 और एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2022 की रिपोर्टें निष्कर्ष निकालती हैं कि इज़राइल की नीतियां इस सीमा को पूरा करती हैं, जिसमें भेदभावपूर्ण कानूनों, गतिशीलता प्रतिबंधों और हत्याओं का हवाला दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने 2022 में कब्जे वाले क्षेत्रों में अपराध की पुष्टि की, एक निष्कर्ष जिसे इज़राइल ने राजनीतिक के रूप में खारिज कर दिया। इन नकली जांचों को नजरअंदाज करने में आईसीसी की अक्षमता—2024 के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद—अमेरिकी प्रतिबंधों से और बढ़ जाती है। SWIFT नेटवर्क, अमेरिकी क्षेत्राधिकार के तहत, वैश्विक बैंकों को जर्जों के खातों को फ्रीज करने के लिए मजबूर करता है, जबकि मास्टरकार्ड/वीजा क्रेडिट सेवाओं को निलंबित करता है, और उड़ान निषेध सूची में शामिल करना यात्रा को प्रतिबंधित करता है, जैसा कि खान के मामले में देखा गया। आईसीसी और संयुक्त राष्ट्र इसे न्याय पर हमले के रूप में निंदा करते हैं, यूरोपीय संघ एक अवरोधक क़ानून का प्रस्ताव देता है, फिर भी इज़राइल की चोरी बनी रहती है।

इज़राइल का आईसीसी के क्षेत्राधिकार से बचना एक सोची-समझी रणनीति है, जो पूरकता का दुरुपयोग करके एक दो-स्तरीय कानूनी प्रणाली को बनाए रखती है जो फिलिस्तीनियों को दबाती है जबकि बसने वालों और सैनिकों को बचाती है। हिंद राजब और राफा के नरसंहार, उनके उजागर झूठ और अपराधियों की मुक्ति, और अमेरिकी प्रतिबंध जो आईसीसी के जजों को पंगु बनाते हैं, इस शासन के निर्विवाद सबूत हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए—स्वतंत्र जांचों की मांग, जवाबी प्रतिबंध लगाना और आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करना—इस अपराध जैसी संरचना को ध्वस्त करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए।